

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 01/2019 प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम

नरपत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

1. पूर्ण लाल पुत्र कल्याण जाति जोगी निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. श्रीमती मगन कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा
3. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा



..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा दिनांक 19.5.2000 जिसके तहत अप्रार्थी सं0 01 को वाके ग्राम खुरी खुर्द में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की पास की भूमि खसरा नंबर 362 में से 0.75 है. भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थित-1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से

3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 08.05.2024

1.संक्षिप्त वृत्तांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.5.2000 को ग्राम खुरी खुर्द के खसरा नंबर 362 में से 0.75 है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 पूर्ण लाल जोगी को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू-आवंटन नियम-1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

2.प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। तलब किया गया।

3.अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि वाके ग्राम खुरी खुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 362 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए के मध्य से 50 गज की दूरी पर स्थित है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 गज की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। किन्तु आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा ने बिना कोई उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना कोई जांच किये बिना विधि विरुद्ध तरीके से आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए फ़ॉड व धोखे से कानून विरोधी आचरण करके और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ए के मध्य से 50 गज की दूरी में स्थित ग्राम खुरी खुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 362 में से 0.75 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 19.5.2000 को अप्रार्थी सं0 1 को कर दिया तथा अप्रार्थी सं0 1 ने बिना अपना कब्जा हुए बिना ही उक्त भूमि का अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय कर दिया। भू आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश दिनांक 19.5.2000 विधि विरुद्ध प्रक्रिया व नियमों के विपरीत है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करके उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गई है ना ही उद्घोषणा की तामील करवाई गई है। बिना उद्घोषणा की तामील किये बिना व बिना कोई जांच किये किया गया उक्त आवंटन आदेश निरस्तनीय है। कानूनन आवंटन नियमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 गज की दूरी तक की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। जबकि प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए के मध्य से 50 गज की

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा



समिति द्वारा अप्रार्थी सं० १ को आवंटन आदेश दिनांक १९-०५-२००० से खसरा नम्बर ३६२ में से ०.७५ है० भूमि का आवंटन किया गया तथा खसरा नम्बर ३६२ से अन्य कई व्यक्तियों को भी उक्त भूमि में से आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा जान बूझकर गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी सं० १ व २ को हैरान व परेशान करने की गरज से एवम् अप्रार्थी सं० १ व २ की उक्त भूमि को हड़प करने की गरज से पेश किया गया है। आवंटन आदेश दिनांक १९-०५-२००० आवंटन नियमों की पालना करते हुए पारित किया गया है, जिसमें फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन से उक्त आवंटन आदेश पारित नहीं किया गया है जबकि उक्त आवंटन आदेश मजमे आम में पूर्ण कोरम के साथ आवंटन कमेटी के द्वारा किया गया है। उक्त आवंटित भूमि पर पूर्वजो के समय से ही आवंटी अप्रार्थी सं० १ का कब्जा चला आ रहा था। इसी कारण से आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी सं० १ को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन की गई वाके ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खसरा नम्बर ३६२ में से ०.७५ है० भूमि आवंटन आदेश दिनांक १९-०५-२००० के द्वारा की गई है उक्त भूमि के नये नम्बर ३६२/४ रकबा ०.७५ है० बनाये गये है तथा प्रार्थी नरपतसिंह को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी आवंटन आदेश होने के दिन से ही थी परन्तु प्रार्थी नरपतसिंह द्वारा दिनांक २२-०१-२०१९ को उक्त उजरात आवंटन आदेश दिनांक १९-०५-२००० से लगभग १९ वर्ष बाद अप्रार्थी सं० १ को खातेदारी अधिकार मिल जाने के पश्चात पेश किये गये है जो कानूनन माननीय न्यायालय को आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात उजरात सुनने का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक १९-०५-२००० को वाके ग्राम खुरी खुर्द में अप्रार्थी संख्या १ पूर्णलाल को खसरा नम्बर ३६२ में से ०.७५ है० भूमि का आवंटन आदेश आवंटन नियमों की पालना करते हुए किया गया है। खसरा नम्बर ३६२/४ रकबा ०.७५ है० राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० १ के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज होने के पश्चात अप्रार्थी सं० १ द्वारा दिनांक १६-०४-२००८ को अप्रार्थी सं० २ को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया है। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से पूर्व से ही अप्रार्थी सं० १ का कब्जा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दिन तक था तथा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दिन से उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं० २ का कब्जा है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी पूर्ण लाल के हक में दिनांक १९-०५-२००० को होने के पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तरण अप्रार्थी सं० १ के हक में खुला तथा उसके पश्चात अप्रार्थी सं० १ का उक्त भूमि पर कब्जा होने तथा आवंटन शर्तों की पालना करने पर गैर खातेदारी का २६० दिनांक ३०-०१-२००४ को उक्त नामान्तरण तहसीलदार दौसा खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी सं० १ द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उक्त नामान्तरण की अपील संख्या ०५/२००० पूर्णमल बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक २५-०४-२००७ को उक्त अपील का निर्णय पारित कर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि प्रार्थी आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा होने अथवा नहीं होने की जांच करे तथा प्रार्थी खातेदारी अधिकारों का अपात्र था तो नामान्तरण भरकर पेश करने वाले पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे तथा खातेदारी अधिकारों का पात्र हैं तो नामान्तरण निरस्त करने वाले आई एल आर व तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण संख्या १५/२००७ उनवानी पूर्णमल बनाम सरकार में दिनांक २०.७.२००७ को अन्तिम निर्णय पारित फरमाया जाकर आदेश दिये गये कि नामान्तरण संख्या २६० में अंकित भूमि खसरा नम्बर ३६२ रकबा ०.७५ है० में से एन एच ११ ए में परिसीमन क्षेत्र में ०.०२ है० कम करते हुए शेष भूमि का रकबा ०.७३ है० के संबंध में गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने व खातेदारी अधिकारों की पात्रता रखने के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना स्वीकार किया गया। न्यायालय तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक २०.७.२००७ को निर्णय पारित करने से

.....निरंतर ४ पर

जिला कलेक्टर, दौसा



पूर्व न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त एन एच 11 ए के उक्त आवंटित भूमि के समीप अथवा नजदीक होने के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर से जांच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का तथा गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 16-07-2007 में पटवारी हल्का तथा गिरदावर ने अपनी जांच में यह तथ्य साबित पाया कि उक्त आवंटित भूमि खसरा नम्बर 362/4 का लगभग 0.02 है० भाग एन एच 11 ए की चौड़ाई परिसीमा क्षेत्र में आता है और यह भी अभिशंषा की कि उक्त प्रकरण में गैर खातेदार को आवंटित भूमि की गैर खातेदारी में से सडक परिसीमन रकबा 0.02 है० को छोड़कर शेष भूमि की खातेदारी दी जा सकती है तथा गैर खातेदार द्वारा आवंटन नियमों की शर्तों की पालना की जा रही है मौके पर कब्जा काश्त है एवम् गैर खातेदार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता रखता है। इस प्रकार माननीय न्यायालय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 20-07-2007 में तहसीलदार दौसा द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के मंगवाई जाकर उक्त गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तरण संख्या 260 का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 21-07-2007 को गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये तथा अप्रार्थी सं० 1 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.75 है० भूमि में से 0.02 है० भूमि एन एच 11 ए की सीमा में छोड़ कर शेष भूमि के खातेदारी अधिकार तहसीलदार भू अभिलेख दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किये गये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा था। उसके पश्चात अप्रार्थी सं० 1 ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 16-04-2008 को उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया गया। वर्तमान में वाके ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खसरा नम्बर 362/4 की एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार अप्रार्थी सं० 2 है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं० 2 का कब्जा काश्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उजरात खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने बहस जारी रखते हुए दलील दी कि पूर्व में एन एच 11 ए खसरा नम्बर 218 में होकर गुजर रहा था लेकिन सन 1991 में दौसा जिला बनने के पश्चात उक्त एन एच 11 ए का विस्तार किया गया तथा खातेदारान की भूमि को अवाप्त कर उक्त एन एच 11 ए को पश्चिम दिशा की ओर अधिक बढ़ाकर भूमि अवाप्त कर एन एच 11 ए का निर्माण किया गया जिसमें खसरा नम्बर 205/1, खसरा नम्बर 203/1, खसरा नम्बर 219/1, खसरा नम्बर 202/1 में अवाप्ति की जाकर भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के खाते में खसरा नम्बर 203/1 रकबा 0.54 है० गै०मु०सडक, खसरा नम्बर 205/1 रकबा 0.33 है० गै०मु०सडक, खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.75 है० गै०मु०सडक अवाप्त की जाकर खातेदारी में दर्ज की गई एवम् वर्तमान में खसरा नम्बर 218 रकबा 2.23 है० गै०मु० सडक जो सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा के खाता संख्या 282 में दर्ज रिकॉर्ड है पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए न बनकर पश्चिम दिशा की ओर भूमि अवाप्त कर बनाया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.73 है० भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के परिधि के अन्दर नहीं आती है प्रार्थी द्वारा जो उजरात श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है उसकी स्वयं की भी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 202/2 रकबा 1.81 है० भूमि एन एच 11 ए राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है उक्त भूमि मूल नम्बर 362 में से अन्य आवंटियों को आवंटित की गई है जिनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अन्य खातेदारान की भी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है जिनके खसरा नम्बर 205/2, 203/2, 362/2, 362/3, 362/1672, 362/6, 362 है। उपरोक्त नम्बर भी उक्त ग्राम में एन एच 11 ए के समीप है। ग्राम खुरी खुर्द में स्थित खसरा नंबर 362 रकबा 2.67 है० में से अप्रार्थी सं० 1 को 0.75 है० भूमि का आवंटन दिनांक 19.5.2000 को आवंटित की गई थी जिससे खसरा नंबर 362/4 की खातेदारी अप्रार्थी सं० 1 को दी गई जिसके संबंध में प्रार्थी नरपतसिंह, आरबीजे (8) 2001 पेज 125 आरबी, आरबीजे 1995 (2) पेज 780 एचसी की प्रतियां पेश की

द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय दौसा में एक वाद उनवानी नरपतसिंह बनाम पूर्णलाल वगै० अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दावा सं० १०५/२०२३ टी०आई० सं० १०६/२०२३ पेश किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में प्रा०पत्र १४(४) में वर्णित भूमि के आवंटन आदेश दिनांक १९.५.२००० को अवैध व प्रभावशून्य घोषित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने के कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। भू आवंटन नियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात प्रा.पत्र १४(४) उजरात पेश नहीं किये जा सकते हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० १ से २ ने उक्त कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी २०२३(१)पेज ५५९ आरबी, २०२१ आरबीजे पेज ७४७ आरबी, आरआरडी २०१८ पेज ४७९ एचसी, आरआरटी २०१७(२)पेज ९७२ आरबी, २०११(१)आरआरटी पेज ३८३ एचसी, आरआरडी २००८ पेज १२५ आरबी, आरआरडी २००७ पेज ७१३ आरबी, आरआरडी २००६ पेज १३५ आरबी।

५. राजकीय अधिवक्ता की ने दलील दी कि ग्राम खुरी खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर ३६२ रकबा ०.७५ है० भूमि पूर्ण कोरम में अप्रार्थी पूर्णलाल पुत्र कल्याण जोगी को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक १९.५.२००० को विधिवत व कानूनन तरीके से आवंटित हुई थी। आवंटी पूर्णलाल का आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व व आवंटन के पश्चात भी निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी पूर्णलाल के द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों की पालना करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण सं० २६० भरकर तस्दीक हेतु तहसीलदार दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक २०.१.२००४ को निरस्त कर दिया गया। उक्त नामान्तरण की अपील मा० न्यायालय अति० जिला कलेक्टर दौसा में प्रस्तुत की गई जिस पर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक २५.४.२००७ के द्वारा अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक २०.१.२००४ को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया कि आवंटी के कब्जा काश्त की जांच की जाकर खातेदारी अधिकार के संबंध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार भूमि एन०एच०११ के समीप होना तथा खसरा नंबर ३६२/४ रकबा ०.७५ है. में से लगभग ०.०२ है० भूमि सडक परीसीमा क्षेत्र में आना उल्लेखित किया गया तथा आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों की पालना किय जाना तथा भूमि पर कब्जा काश्त होना माना जाकर ०.७३ है० भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। प्रार्थी द्वारा नितान्त गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा १४(४) आवंटन नियम १९७० पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र १४(४) आवंटन नियम १९७० को निरस्त फरमाया जावे।

६. हमने उभपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक १९.५.२००० को कैंप बापी में आवंटी पूर्णलाल पुत्र कल्याण जाति

.....निरंतर ६ पर


जिला कलेक्टर, दौसा



जोगी निवासी खुरी खुर्द को ग्राम खुरी खुर्द में स्थित आराजी खसरा नंबर ३६२ में से ०.७५ है० भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटनी द्वारा भूमि आवंटन कराने बाबत आवेदन पत्र भरकर आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आवंटन की गई थी।

६.१ पत्रावली में शामिल मूल आवंटन अभिलेख के अवलोकन से अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन गलत सिद्ध होता है कि आवेदन पत्र में पहले ०.५० है० भूमि का आवंटन करके उस पर उपखंड अधिकारी ने हस्ताक्षर किये गये हैं, बाद में उस पर लाईन खींच कर ०.७५ है० भूमि लिखी गई है।

६.२ पत्रावली में शामिल नकल खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी सं० २ मगन कंवर का संवत् २०६३ से २०७९ तक निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

६.३ आवंटित भूमि पर प्रार्थी का अथवा प्रार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

६.४ हम अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के से सहमत हैं जिसके अनुसार कपट कारित कर एवं तथ्य छिपाकर आवंटन प्राप्त करने पर भूमि का आवंटन खातेदारी प्राप्त होने के उपरांत भी निरस्त किया जा सकता है।

६.५ साथ ही प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश दौसा में एक अन्य वाद उनवानी नरपतसिंह बनाम पूर्णलाल वगै० अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दावा सं० १०५/२०२३ टी०आई० सं० १०६/२०२३ पेश किया गया है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है।

६.६ प्रार्थी का मुख्य उज्र यह है कि आवंटित भूमि सडक सीमा के ५० गज के भीतर है। न्यायालय द्वारा इस बाबत तहसीलदार दौसा से तलब रिपोर्ट क्रमांक:५९४ दिनांक ९.२.२०२३ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर ३६२/४ की भूमि एन.एच. के मध्य से २९ मीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम १९७० के नियम ४(च) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार " राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित कोई अन्य सडक के लिए भारतीय सडक कांग्रेस के मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट सीमाएं या किसी अधिनियम या केन्द्रीय या राज्य सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों या सडक के केन्द्र में ४५ मीटर जो भी अधिक हो, में यथा विनिर्दिष्ट सीमाएं) में स्थित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।" आवंटन की मूल पत्रावली में पटवारी द्वारा उक्त खसरे के संबंध में यह रिपोर्ट की गई है कि यह भूमि एन.एच.११ ए से सिरा लगती हुई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि तत्समय जब इस भूमि का आवंटन किया गया था, तब भी यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में था, एवं प्रश्नगत भूमि सडक से २९ मीटर की परिधि में स्थित है।

६.७ प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी को खसरा नंबर ३६२/२ की भूमि का आवंटन किया गया है किन्तु नामान्तरण गलत तरीके से खसरा नंबर ३६२/४ किया जाकर

.....निरंतर ७ पर

जिला कलेक्टर, दौसा

तस्दीक किया गया है जो कि फ़ॉड की श्रेणी में आता है। आवंटन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ३६२/२ में से ०.८५ है० आवंटन हेतु निवेदन किया गया था किन्तु उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा किया गया था जिसके खसरा नंबर ३६२ में से ०.७५ है. रकबे का आवंटन ३६२/४ बनाये गये थे।

६.८ इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक २५.४.२००७ भी महत्वपूर्ण है जिसमें उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में नामान्तरण के आदेश निरस्त कर तहसीलदार दौसा को रिमांड कर प्रकरण में पुनः सुनकर आदेश पारित करने हेतु निर्णय दिया था जिसके पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक २१.७.२००७ खसरा नंबर ३६२/४ रकबा ०.७५ है० में से एन.एच.११ ए के सीमा में आ रहे रकबा ०.०२ है को कम करते हुए शेष भूमि ०.७३ है. के खातेदारी अधिकार दिये जवने हेतु स्वीकृत किया एवं नियमानुसार सडक सीमा रकबे के संबंध में नियम १४(४) की कार्यवाही प्रस्तावित कर पालना की जावे के आदेश प्रदान किये।

७. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा १४(४) आवंटन नियम १९७० आंशिक स्वीकार किया जाता है।

७.१ मूल आवंटन आदेश दिनांक १९.५.२००० को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि एन.एच.११ ए के मध्य से ४५ मीटर भूमि तक श्री पूर्ण लाल जोगी पुत्र कल्याण जोगी को खसरा संख्या ३६२ में से प्रदान की गई गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार जिसके नये खसरा नंबर ३६२/४ बने है, को निरस्त किया जाता है।

७.२ खसरा नंबर ३६२/४ का रकबा जो एन.एच.११ ए के मध्य से ४५ मीटर भूमि में स्थित है उसको राजकीय भूमि दर्ज किया जाये।

७.३ शेष भूमि का आवंटन यथावत बहाल रखा जाता है।

७.४ तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक ०८ मई, २०२४ को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में ३० दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

